

प्रेषक,

ओ०पी०तिवारी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
श्रीनगर (पौडी)।

देहरादून: दिनांक 21 मार्च, 2011

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में के०एल०पालीटेक्निक, रुड़की के कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु चतुर्थ त्रैमास के लिए धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-114कैम्प/नि०प्रा०शि०/एका०तीन-01/2010-11, दिनांक 23.02.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन सहायता प्राप्त के०एल० पालीटेक्निक, रुड़की के कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में चतुर्थ त्रैमास (दिनांक 01.01.2011 से 31.03.2011 तक) के लिये आयोजनेत्तर पक्षान्तर्गत 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद में ₹ 62,50,000/- (रुपये बासठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय किये जाने की हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2010-11 में देय 30 प्रतिशत वेतन/पेंशन एरियर की अन्तिम किश्त की धनराशि का भुगतान शासन के वित्त विभाग के अग्रिम आदेशों के बाद ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण /व्यय संस्था को पूर्व अवमुक्त धनराशि (वेतनादि हेतु) में पूर्ण व्यय होने के उपरान्त आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार ही किया जायेगा।

3- व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों हेतु पूरे वर्ष के सम्भावित व्यय की फेजिंग कर कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करायेगें तब लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा।

4- किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का क से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतनादि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तदनुसार विशेष आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित कि जाय।

6- अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तान्कित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियाँ शासनादेश संख्या बी-2-2337/97 दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये।

7- बजट नियंत्रक अधिकारी बी.एम-17 पर आवंटन सम्बन्धी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण-वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियाँ पूर्व निर्गत शासनादेशों के क्रम में जारी किया जाय अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

8- विभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियाँ सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

9- अवचनबद्ध मदों में धनराशि के आहरण का प्रस्ताव औचित्य सहित शासन की सहमति हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे एवं शासन की स्वीकृति उपरान्त ही धनराशि आहरित की जायेगी।

10- बजट मैनुअल पैरा-88 में इंगित किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो इस बात को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी.एम-13 पर नियमित रूप से सूचना विलम्बतः 15 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

11- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू स्वीकृति योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

12- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

13- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2203-तकनीकी शिक्षा-104-अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता-03-के0एल0पालीटेक्निक, रुड़की-00-आयोजनेत्तर-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-551NP)/XXVII(3)/2010 दिनांक 18.03.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(ओपी0तिवारी)

उप सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबेरॉय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
3. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पौड़ी/हरिद्वार/रूड़की
5. प्रधानाचार्य, के०एल० पालीटेक्निक संस्थान रूड़की।
6. वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
9. बजट राजकोषीय प्रकोष्ठ सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल

आज्ञा से.

(सुनील सिंह)
अनु सचिव